

## NGO का FCRA पंजीकरण रद्द करना

### प्रलिमिस के लिये:

विदेशी अंशदान वनियमन अधनियम, **NGO**, कंपनी अधनियम, 2013, भारतीय ट्रस्ट अधनियम, 1882, सोसायटी पंजीकरण अधनियम, 1860, NGO-दर्पण प्लेटफॉर्म।

### मेन्स के लिये:

भारत में गैर सरकारी संगठनों का वनियमन, FCRA के प्रमुख प्रावधान।

**स्रोत: द हिंदू**

### चर्चा में क्यों?

दो प्रमुख **गैर-सरकारी संगठनों (NGO)**- सेंटर फॉर पॉलिसी रसिरच (CPR) और वर्ल्ड वज़िन इंडिया (WVI) के लिये विदेशी अंशदान वनियमन अधनियम, 2010 (FCRA) पंजीकरण रद्द किया जाने से भारत में विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने वाले नियमिक प्रदृष्टशय को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

### CPR और WVI के पंजीकरण रद्द करने का क्या कारण है?

- गृह मंत्रालय के अनुसार CPR ने विकास परियोजनाओं के विद्युत कानूनी चुनौतियों प्रस्तुत करने तथा भारत में विदेशी प्रदर्शनों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर भारत के आरथकि हतियों को नुकसान पहुँचाने के लिये विदेशी से प्राप्त अंशदान का दुरुपयोग किया है।
  - उदाहरण के तौर पर वायु प्रदूषण पर CPR की रपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप में करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों के उत्पादन के माध्यम से FCRA मानदंडों का उल्लंघन शामिल है।
- गृह मंत्रालय का दावा है कि विदेशी फंड से ऐसे कार्यक्रम प्रकाशित करना FCRA की धारा 3 का उल्लंघन है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक कथति FCRA उल्लंघन के लिये वर्ल्ड वज़िन इंडिया का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।
  - वर्ष 1986 में अधनियम के तहत पंजीकृत सभी गैर सरकारी संगठनों के बीच WVI सबसे अधिक विदेशी दान प्राप्तकरता है।

### FCRA क्या है?

- पराचय:
  - विदेशी सरकारों द्वारा भारत के आंतरकि मामलों को प्रभावित करने के लिये स्वतंत्र संगठनों की सहायता से किया जाने वाले वित्तीय आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए FCRA को वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान अधनियमित किया गया था।
  - इसे एक संपर्भु लोकतांत्रकि गणराज्य के सदिधांतों के साथ संरेखित करते हुए आंतरकि सुरक्षा पर कसी भी प्रतक्रिया प्रभाव को रोकने के लिये विदेशी अंशदान को वनियमित करने हेतु डिज़िएन किया गया था।
- FCRA का विकास:
  - **2010 संशोधन:** विशिष्ट व्यक्तियों अथवा संघों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृतितथा उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों को सुव्यवस्थिति करने एवं राष्ट्रीय हतियों के लिये हानिकारक गतिविधियों की रोकथाम हेतु संबद्ध योगदान को प्रतिबंधित करने के लिये इसे अधनियमित किया गया था।
  - **2020 संशोधन:**
    - संबद्ध गैर सरकारी संगठनों (NGO) के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा तथा केवल भारतीय स्टेट बैंक के साथ नामित FCRA बैंक खातों के माध्यम से विदेशी अंशदान की प्राप्ति की जा सकेगी।
    - विदेशी अंशदान के घरेलू अंतरण पर पूरण प्रतिबंध।
    - प्रशासनिक व्यय सीमा को 50% से घटाकर 20% किया गया।
- प्रयोज्यता: FCRA विदेशी अंशदान प्राप्त करने के इच्छुक सभी संघों, समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।
  - नियंत्रित मानदंडों के अनुपालन करने पर इसके नवीनीकरण की संभावना के साथ प्रारंभ में इसे 5 वर्षों के लिये वैध किया गया था।
- विदेशी अंशदान के उद्देश्य: पंजीकृत संघ सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आरथकि तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिये विदेशी अंशदान प्राप्त

कर सकते हैं।

■ नगिरानी/अनुश्रवण प्राधिकरण: गृह मंत्रालय

- वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों को वास्तविक समय में सुरक्षा पहुँच के लिये कोर बैंकिंग सुविधाओं वाले बैंकों में खाते संचालित करने का आदेश दिया।
- वर्ष 2023 में MHA ने FCRA-पंजीकृत NGO के लिये नियमों में संशोधन किया जिसके तहत अब उन्हें अपनी वार्षिक विवरणी/रिटर्न में विदेशी अंशदान के उपयोग से सूजति परसिंपत्तिका खुलासा करना आवश्यक हो गया है।

## भारत में NGO को कैसे विनियमित किया जाता है?

■ परचिय:

- जैसा कविशिव बैंक द्वारा परभिषति किया गया है, गैर-सरकारी संगठन उन गैर-लाभकारी संगठनों को संदर्भिति करते हैं जो पीड़ा को दूर करने, गरीबों के हतियों को बढ़ावा देने, प्रयावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास करने के लिये गतिविधियों करते हैं।
- हालाँकि, भारत में NGO शब्द संगठनों के एक व्यापक संप्रेक्षण को दर्शाता है जो गैर-सरकारी, अर्थ या अर्थ सरकारी, स्वैच्छिक या गैर-स्वैच्छिक आदि हो सकते हैं।

■ पंजीकरण एवं विनियमन: मुख्यतः NGO कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत ट्रस्ट, सोसायटी या कंपनी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण और शासन के लिये प्रत्येक फॉर्म के अपने नियम और विनियम हैं।

- **ट्रस्ट:** भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या समकक्ष राज्य कानूनों द्वारा शासित, जिसके लिये चैररी आयुक्त के कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता होती है।
- **सोसायटी:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या इसके राज्य-विशिष्ट विविधियों के तहत सोसायटी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत।
- **धारा 8 कंपनियाँ:** वाणिज्यिक कंपनियों के समान पंजीकृत लेकनि गैर-लाभकारी उद्देश्यों के साथ।

■ NGO-दरपण प्लेटफॉर्म: यह गैर सरकारी संगठनों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सरकारी नकायों के बीच इंटरफेस के लिये स्थान प्रदान करता है।

- यह सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच बेहतर साझेदारी लाने और बेहतर पारदर्शना, दक्षता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से नीतिआयोग द्वारा दी जाने वाली एक नियमित सुविधा है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विनियमन के प्रश्न

?/?/?/?/?:

प्रश्न. क्या सविलि सोसायटी और गैर-सरकारी संगठन आम नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिये लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतमान की चुनौतियों की विचारना कीजिये। (2021)